Torture of children by Delhi Police

1123. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the Indian Express of the 1st July, 1989 regarding merciless torture of some children who were detained by the Delhi Police in connection with a theft case;

(b) whether Government have since made any inquiry into the alleged inhuman behaviour of the police towards the children;

(c) if so, what is the outcome thereof stating the action taken by Government against the policemen;

(d) what measures have been taken by Government to ensure that such merciless torture is not meted out to the children in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. Two separate enquiries were conducted by ACP Headquarter, North-West District and by Vigilance Branch. The charges against the police were not substantiated.

(d) There is a standing order by the Police Commissioner that the police should not take recourse to third-degree methods.

बांध परियोजनाओं और "क्रीड़ा स्थलियों" का विकास

1124. डा. अबरार अहमद खान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी बांध परियोजनायें (टाइगर प्रोजेक्ट) तथा "क्रीड़ा स्थलियां" (गेम्स सैंक्चुअरीज) है तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना व क्षेत्र के संरक्षण रख-रखाव और विकास पर प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार स्थलीवार कितनी कितनी राशि खर्च की गई हैं ; प्रत्येक परियोजना स्थली ने कितना-कितना क्षेत्र घेर रखा हैं तथा प्रत्येक परियोजना स्थली में कितने-कितने जानवर हैं तथा उनकी जातियां क्या हैं; इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) "सवाई माधोपुर टाइगर प्रोजेक्ट का ब्यौरा क्या हैं, उस पर वार्षिक खर्च कितना आता है, वर्तमान में वहां पर बाघों की संख्या कितनी हैं और उनकी बढ़ोत्तरी की वार्षिक दर क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : इस समय देश में 17 बाघ रिजर्व और 397 वन्यजीव अभयारण्य हैं । उनकी स्थिति संलग्न अनुपत्रों में दी गई है। (**देखिए** परिशिष्ट 151 अनुपत्र संख्या 83 और 84)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांध रिज़र्वों और वन्यजीव अभयारण्यों की सुरक्षा, रखरखाव और विकास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया हैं (**देखिए** परिशिष्ट 151 अनुपत्र सं० 85) प्रत्येक बाघ रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र अनुपत्र में दिया गया हैं (**देखिए** परिशिष्ट 151 अनुपत्र सं० 86)। प्रत्येक बाघ रिजर्व अभयारण्य के पशुओं की प्रमुख प्रजातियों के बारे में उपलब्ध सूचना अनुपत्र में दी गई हैं। (**देखिए** परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 87) इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वासस्थलों में रहने वाले वन्यजीवों की विविधता को देखते हुए उनकी संख्या का पता लगाना संभव नहीं हैं।

(ग) सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर बाघ रिजर्व के ब्यौरे अनुपत्र

में दिए गए हैं (देखिए परिशिष्ट 151, अनुपत्र संख्या 88)

Oil spillage in Arabian Sea

1125. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a major oil spillage that took place in the Arabian Sea is fast moving in the direction of Bombay's coast line; and

(b) if so, what are the details thereof and what steps have been taken by Government to check pollution of Indian sea waters and to save the marine life?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) The small spill of two tonnes leaked near the Bombay Coast was noticed and controlled. The big spill of 5500 tonnes occurred at the place of accident some 725 km. off the Western Coast has not reached the Bombay coast so far. Indications are that this slick has disintegrated and moved down south will clear of the Indian coast.

(b) Various steps taken by the Government in this regard are as follows:

(i) the Indian Coast Guard went into action immediately, assisted by the Maharashtra Pollution Control Board;

(ii) a high level meeting was held in Bombay by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, to chalk out the strategies to be followed;

(iii) regional Contingency Committee which already functions under the Indian Coast Guard were directed to locate the oil slick and also to implement the action plan with them;

(iv) National Remote Sensing Agency, Hyderabad, was also assigned the task of locating the oil slick through the satellite; and

(v) National Institute of Oceanography's vessel collected the samples to study the effects on marine life.

गुजरात में कपड़ा मिलों से संबंधित त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशें

1126. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री 27 अप्रैल, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 440 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा 22 जून, 1989 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए गुजरात राज्य के वस्त्र उद्योग के संबंध में त्रिपक्षीय समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : जैसा कि पिछले उत्तर में उल्लेख किया गया था, त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों की यथोचित कार्रवाई हेतु समीक्षा की गई थी। कुछ मामलों में उन पर कार्रवाई पहले ही हो गई है जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है कुछ मामलों में कार्रवाही राज्य सरकारों को ही करनी थी त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष के मंत्रालयवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं --

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र नीति के क्रियान्वयन के अध्ययन हेतु एक समिति पहले ही गठित की गई है इसी प्रकार, रुग्ण बन्द पड़ी मिलों के मामलों की जांच करने के लिये गठित नोडीय अभिकरण ने गुजरात में बन्द पड़ी 36 मिलों में से 20 मिलों के मामलों की जांच कर ली